



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, 15 नवम्बर, 1975 (कार्तिक 24, 1897)
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1975 (KARTIKA 24, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 1 अक्टूबर 1975 तक प्रकाशित किए गए हैं—
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 1st October 1975:—

अंक Issuc No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------

—शून्य—
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाईन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र नियंत्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 799	जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	पृष्ठ 3137
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1733	भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3955
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	103	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	489
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1437	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	9597
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	767
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और		भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1985
		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	201

CONTENTS

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PAGE 799	(other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	PAGE 3137
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1733	PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3955
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	103	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	489
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1437	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Officers of the Government of India	9597
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	767
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India		PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1985
		PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	201

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी विधि बोर्ड

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 अक्तूबर 1975

आदेश

सं० 7(11)-75-सी०एल०-II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का I) की धारा 209 क के खण्ड (1) के उपखण्ड (2) के अनुसरण में, कम्पनी विधि बोर्ड, एतद्वारा, कम्पनी कार्य विभाग में भारत सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को कथित धारा 209क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करता है :—

1. श्री एस० एस० सेठ, निरीक्षण अधिकारी, कम्पनी विधि, बोर्ड, कानपुर
2. श्री सी० आर० मेहता, उप-निदेशक, निरीक्षण, कम्पनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली।

2. कम्पनी विधि बोर्ड, एतद्वारा, श्री एस० एस० सेठ के पक्ष में पहिले जारी किये विधि मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग के आदेश संख्या 51/1/65-सी० एल० 2, दिनांक 7 फरवरी, 1966 तथा दिनांक 7 मार्च, 1967 के आदेश संख्या 51/1/65-सी० एल० 2 द्वारा यथा संशोधित प्राधिकरण को रद्द करता है।

3. कम्पनी विधि बोर्ड, औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 1970 के आदेश संख्या 53/1/70-सी० एल०-II द्वारा श्री सी० आर० मेहता के पक्ष में पहिले जारी किये गये प्राधिकरण को रद्द करता है।

टी० एस० श्रीनिवासन,
संयुक्त निदेशक, निरीक्षण एवं पब्लिक
उप सचिव, कम्पनी विधि बोर्ड

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 सितम्बर 1975

संकल्प

सं० 6/10/75-एफ(पी)—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/29/58-एफ(पी) दिनांक 5 फरवरी, 1959 का अधिग्रहण करते हुए, चलचित्र अधिनियम,

1952 (1952 का 37) की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा तदनुसूची राज्य कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार फिल्मों को वैज्ञानिक फिल्मों, शिक्षा संबंधी फिल्मों, समाचार तथा सामयिक घटनाओं की फिल्मों, डाक्यूमेंटरी फिल्मों या देशी फिल्मों के रूप में स्वीकृत करने के प्रयोजन हेतु बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के फिल्म सलाहकार बोर्डों के कार्य संचालन के संबंध में निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं। ये नियम तत्काल प्रवृत्त होंगे।

नियम

1. तीन फिल्म सलाहकार बोर्ड होंगे अर्थात् बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक-एक। प्रत्येक फिल्म सलाहकार बोर्ड का कार्य चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा तदनुसूची राज्य नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार वैज्ञानिक फिल्मों, शिक्षा संबंधी फिल्मों, समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्मों, डाक्यूमेंटरी फिल्मों या देशी फिल्मों के रूप में स्वीकृत करने के लिए फिल्मों की उपयुक्तता के बारे में केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करना होगा।

2. प्रत्येक बोर्ड में कम से कम सात सदस्य निम्नानुसार होंगे :—

(क) जब तक चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1974 प्रवृत्त नहीं होता तब तक फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित फिल्म सेंसर बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड का अध्यक्ष होगा। अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद, फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित फिल्म सेंसर बोर्ड का कोई पूर्णकालिक सदस्य बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(ख) जब तक चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1974 लागू नहीं होता तब तक प्रत्येक केन्द्र पर फिल्म सेंसर बोर्ड का प्रादेशिक अधिकारी और फिल्म सेंसर बोर्ड के सलाहकार पैनल का एक सदस्य अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित फिल्म सेंसर बोर्ड के दो असंसद होंगे।

- (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित कम से कम चार और सदस्य जिनमें फिल्मों की और फिल्म निर्माण की जानकारी रखने वाला कम से कम एक व्यक्ति और एक शिक्षा शास्त्री भी होंगे।

प्रत्येक केन्द्र पर फिल्म सेंसर बोर्ड का प्रादेशिक अधिकारी बोर्ड का सचिव होगा।

स्पष्टीकरण :-

प्रादेशिक अधिकारी की अनुपस्थिति में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का अपर प्रादेशिक अधिकारी या सहायक प्रादेशिक अधिकारी बोर्ड के सचिव के रूप में काम करेगा।

3. पदेन सदस्यों को छोड़ कर अन्य सदस्यों का कार्य काल दो वर्ष होगा।
4. नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय बोर्ड के किसी भी सदस्य की सदस्यता को उस नियम में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले समाप्त कर सकती है।
5. बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए उतना यात्रा भत्ता दिया जा सकता है जितना केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित करे।
6. बोर्ड के किसी काम या कार्यवाही पर बोर्ड में कोई रिक्ति होने या उसके गठन में कोई लुटि होने के आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी।
7. बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गए सदस्य द्वारा की जायेगी।
8. बोर्ड का कोरम तीन होगा।
9. बोर्ड की बैठक आमतौर पर सप्ताह में एक बार होगी, परन्तु अध्यक्ष जब भी आवश्यक समझेंगे बोर्ड की बैठक बुला सकेंगे।
10. कोई भी व्यक्ति जो यह चाहे कि बोर्ड नियम-1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी फिल्म की उपयुक्तता पर विचार करें, बोर्ड के सचिव को लिखित में एक आवेदन पत्र भेजेगा जिसमें फिल्म का नाम, उसकी लम्बाई, निर्माता का नाम और ऐसा अन्य व्यौरा देगा जिसकी बोर्ड को आवश्यकता हो।
इन नियमों के प्रयोजन के लिए 35 मि० मी० में 608 मीटर से अधिक लम्बाई की फिल्मों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
11. बोर्ड द्वारा फिल्म की जांच करने के बाद, उपस्थित प्रत्येक सदस्य की यह राय लिखी जायेगी कि :-

- (क) फिल्म, वैज्ञानिक फिल्म, शिक्षा संबंधी फिल्म, समाचार तथा सामयिक घटनाओं की फिल्म, डाकुमेंटरी फिल्म या देशी फिल्म के रूप में स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त है; या

- (ख) फिल्म उसमें विनिर्दिष्ट काट-छांट या उपान्तरण करने पर किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी में स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त समझी जाएगी; या

- (ग) फिल्म उक्त किसी भी श्रेणी में स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

12. बोर्ड की राय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत और बराबर मत होने की दशा में पीठासीन अधिकारी की राय के अनुसार होगी।

- 13(क) यदि बोर्ड की राय यह हो कि फिल्म, वैज्ञानिक फिल्म, शिक्षा संबंधी फिल्म, समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म, डाकुमेंटरी फिल्म या देशी फिल्म के रूप में स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त है तो बोर्ड के अध्यक्ष बोर्ड की राय के अनुसार केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेंगे।

- (ख) यदि बोर्ड की राय नियम 11 के खंड (ख) या खंड (ग) के अनुसार हो तो फिल्म सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आवेदक को बोर्ड की राय लिखित में सूचित करेंगे और वह तिथि निर्धारित करेंगे जो ऐसी सूचना देने वाले पत्र की तारीख से सात दिन के बाद की नहीं होगी। आवेदक यदि चाहे तो उस तिथि तक बोर्ड की राय के विरुद्ध प्रत्यावेदन भेज सकता है।

- (ग) इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के निकल जाने या प्रत्यावेदन के प्राप्त होने पर, फिल्म सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बोर्ड की राय के अनुसार केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेंगे और आवेदक के प्रत्यावेदन को केन्द्रीय सरकार को भेजेंगे।

- (घ) यदि आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट काट-छांट या उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जायेगा तो फिल्म सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष यह तसल्ली कर लेने के बाद कि ऐसी काट-छांट या रूपान्तरण कर लिए गए हैं, बोर्ड की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजेंगे।

14. (क) बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार, यदि नियम 13 के उप-नियम (ख) के अन्तर्गत कोई प्रत्यावेदन किया गया हो तो उस पर विचार करने और

ऐसी पूछताछ करने के बाद जो वह जरूरी समझे, फिल्म को नियम 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में उपयुक्त फिल्म के रूप में स्वीकार कर सकती है या मामले में ऐसे आदेश पास कर सकती है जो वह उपयुक्त समझे।

(ख) उपयुक्त नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, फिल्म साहकार बोर्ड से सलाह किए बिना किसी भी फिल्म को नियम 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में शामिल करने के लिए उपयुक्त फिल्म के रूप में स्वीकार कर सकती है।

15. नियम-1 में विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत फिल्में भारत के राजपत्र में अधिसूचित की जायेंगी और साथ में आवेदन का नाम, फिल्म का नाम, निर्माता का नाम, फिल्म जिस रूप में स्वीकृत हुई है उस रूप में उसकी लम्बाई और उसकी श्रेणी भी दी जायेगी।

एम० एम० मुरशेद,
संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 1975

संकल्प

विषय— छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों तथा नगरों की आयोजना तथा विकास पर विचार करने के लिये कार्यकारी दल (टास्क फोर्स) की नियुक्ति।

सं० के०-14011/45/75-न० वि०-II—अनियोजित शहरी विकास की समस्याओं, विशेषकर छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों में तथा ऐसे नगरों के स्थानीय प्रशासनों तथा नगरीय विकास सम्बन्धी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर भारत सरकार विचार करती रही है। अतः, छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों तथा नगरों की आयोजना तथा विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल (टास्क फोर्स) की नियुक्ति करने का निर्णय किया गया है। कार्यकारी दल (टास्क फोर्स) के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. फो० विजीत घोष,
आयोजना तथा वास्तु शिल्प स्कूल,
नई दिल्ली। संयोजक
2. प्रो० देव राज,
भूतपूर्व निदेशक,
नगरीय अध्ययन केन्द्र,
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली। सदस्य
3. प्रो० गिरिजापति मुखर्जी,
भूतपूर्व अध्यक्ष,
नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन,
नई दिल्ली। सदस्य

4. श्री आर० गोपालस्वामी,
संयुक्त सचिव,
निर्माण और आवास मंत्रालय और अध्यक्ष
नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन,
नई दिल्ली। सदस्य

2. कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) आजादी के बाद से नगरों तथा शहरों के विकास की पद्धति का सामान्य मूल्यांकन करना।

(ख) स्थानीय प्रशासनों तथा नगरीय विकास सम्बन्धी कानूनों पर विचार करना तथा छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के आयोजित विकास में सहायता करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए इन कानूनों में समोचित संशोधन करने के सुझाव देना।

(ग) जोन बनाने, सेट बैकों, भवन नियन्त्रण सम्बन्धी मामलों तथा ऐसे अन्य सम्बन्धित मामलों के विषय में भार्ग-निदेशन तथा विनियमन बनाना।

3. नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन, नई दिल्ली आवश्यक लिपिकीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करेगा।

4. कार्यकारी दल से अनुरोध है कि वह अपनी रिपोर्ट छः महीनों के अन्दर दें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों आदि को भेज दी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वी० आर० अय्यर,
अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर 1975

सं० पी०-18025/14/75-फैक०—भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2/11/70-फैक०, दिनांक 31 अक्टूबर, 1970 का संशोधन करने हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के नियमों और विनियमों के नियम 7 (ख) के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट जनरल के० एस० मरेवाल को इसके द्वारा श्री बागल राम तुलपुले, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, के स्थान पर उक्त परिषद् के शासी बोर्ड के चेयरमैन होने के लिए नामित किया जाता है।

हंस राज छाबड़ा,
उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 1975

सं. यू-16011/1/72-डब्ल्यू. ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4 (iv) और (vi) के साथ पढ़े गए नियम 3(ख) के अनुसरण में भारत सरकार इसके द्वारा प्रो० वी० बी० सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री एस० एन० रानाडे के स्थान पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार, 20 दिसम्बर 1958/29 अग्रहायण, 1880 के भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय का, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सख्या

ई० एण्ड पी० 4(24)/58, दिनांक 12 दिसम्बर, 1958 में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे :—

वर्तमान प्रविष्टि :—

“13. श्री एस० एन० रानाडे,
निदेशक, दिल्ली समाजकाय विद्यालय,
दिल्ली।”

के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी :—

“13. प्रोफेसर वी० बी० सिंह,
अर्थशास्त्र विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ”

जे० सी० सक्सेना, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(COMPANY LAW BOARD)

New Delhi-1, the 18th October 1975

ORDER

No. 7(11)/5-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of Clause (I) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (I of 1956), the Company Law Board hereby authorises the following Officers of the Government of India, in the Department of Company Affairs, for the purposes of the said section 209A :—

1. Shri S. S. Seth, Inspecting Officer, Company Law Board, Kanpur.
2. Shri C. R. Mehta, Deputy Director, Inspection, Company Law Board, New Delhi.

2. The Company Law Board hereby revokes the authorisation earlier issued in favour of Shri S. S. Seth vide the Ministry of Law, Department of Company Affairs Order No. 51/1/65-CL.II, dated the 7th February, 1966 as modified by the Order No. 51/1/65-CL.II, dated the 7th March, 1967.

3. The Company Law Board further revokes the authorisation earlier issued in favour of Shri C. R. Mehta, vide the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, Department of Company Affairs Order No. 53/1/70-CL.II, dated the 25th February, 1970.

(T. S. SRINIVASAN

Joint Director of Inspection and *Ex-Officio*
Deputy Secretary to the Company Law Board.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCAST- ING

New Delhi, the 12th September 1975

RESOLUTION

No. 6/10/75-F (P).—In supersession of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 1/29/58-F (P), dated the 5th February, 1959, the following rules are notified in regard to the working of the Film Advisory Boards at Bombay, Calcutta and Madras for the purpose of approval of films as scientific films, films in-

tended for educational purposes, films dealing with news and current events, documentary films or indigenous films in accordance with the directions issued by the Central Government under sub-section (4) of Section 12 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) and by the various State Government under the corresponding State Laws. These rules shall come into force with immediate effect.

RULES

1. There shall be three Film Advisory Boards one each in Bombay, Calcutta and Madras. The functions of each of the Film Advisory Board shall be to make recommendations to the Central Government regarding the suitability of films for approval as scientific films, films intended for educational purposes, films dealing with news and current events, documentary films or indigenous films in accordance with the directions issued by the Central Government under sub-section (4) of Section 12 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) and by the State Governments under the corresponding State Laws.

2. Each Board shall consist of not less than seven members as follows :—

- (a) Chairman, Board of Film Censors or any member of the Board of Film Censors nominated by him shall be the Chairman till the enforcement of the Cinematograph (Amendment) Act, 1974. After implementation of the Act, a whole time member of the Board of Film Censors nominated by the Chairman shall be the Chairman of the Board.
- (b) Regional Officer of the Board of Film Censors and a member of the Advisory Panel of the Board of Film Censors at each Centre till the enforcement of the Cinematograph (Amendment) Act 1974. After the implementation of the Act, two assessors of the Board of Film Censors nominated by the Central Government.
- (c) Not less than four other members including at least one person with knowledge of films and film making and one educationist, nominated by the Central Government. The Regional Officer of the Board of Film Censors at each Centre shall be the Secretary of the Board.

EXPLANATION : The Additional Regional Officer or the Asstt. R. O. CBFC shall act as Secretary to the Board when the R. O. does not attend.

3. Members other than ex-officio shall hold office for a period of two years.

4. Notwithstanding anything contained in rule 3, the Central Government may at any time terminate the membership of any member of the Board before the expiration of the period specified in that rule.

5. The non-official members of the Board may be paid such travelling allowance for attending meetings of the boards as the Central Government may, from time to time, determine.

6. No act or proceeding of the Board shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Board.

7. Meetings of the Board shall be presided over by the Chairman, and, in his absence, by a member elected by the members present from amongst themselves.

8. The quorum of the Board shall be three.

9. The Board shall ordinarily meet once a week but a meeting of the Board may be called by the Chairman as often as he considers necessary.

10. Any person desiring the Board to consider the suitability of any film for the purpose specified in rule 1 shall send an application in writing to the Secretary of the Board stating the title of the film, its length, the name of the producer and such other particulars as may be required by the Board.

Films with lengths exceeding 608 metres in 35 mm shall not be entertained by the Board for the purpose of these rules.

11. After examination of the film by the Board, the opinion of each member present shall be recorded as to whether :—

(a) the film is suitable for approval as a scientific film, a film intended for educational purposes, a film dealing with news and current events, a documentary film or an indigenous film; or

(b) the film would be suitable for approval in any specific category on carrying out specified excisions or modifications therein; or

(c) the film is not suitable for approval as a film in any of the said categories.

12. The opinion of the Board shall be in accordance with the opinion of the majority of the members present at the meeting and, in the event of a tie, in accordance with the opinion of the presiding officer.

13. (a) If the opinion of the Board is that the film is suitable for approval as a scientific film, a film intended for educational purposes, a film dealing with news and current events or a documentary film or an indigenous film, the Chairman of the Film Advisory Board shall make a recommendation to the Central Government in accordance with the opinion of the Board.

(b) If the opinion of the Board is as in clause (b) or Clause (c) of rule 11, the Chairman of the Film Advisory Board shall communicate the opinion of the Board to the applicant in writing and specify a date, not later than seven days from such communication, within which he may, if he so desires, make a representation against the opinion of the Board.

(c) On expiry of the date so specified or on receipt of the representation, the Chairman of the Film Advisory Board shall make a recommendation to the Central Government in accordance with the opinion of the Board and forward the representation made by the applicant, to the Central Government.

(d) If the applicant agrees to carry out the excisions or modifications specified by the Board, the Chairman of Film Advisory Board shall, after satisfying himself that such excisions or modifications are carried out, forward the recommendation of the Board to the Central Government.

14. (a) On receipt of the recommendation of the Board, the Central Government may, after considering the representation, if any, made under sub-rule (b) of rule 43 and such enquiry as it may consider necessary approve the film as suitable in any category specified in rule 1 or pass such orders in the matter as it deems fit.

(b) Notwithstanding any thing contained in the above rules, the Central Government may, without consulting the Film Advisory Board approve any film as suitable for inclusion in any category specified in rule 1.

15. Films approved by the Central Government in any of the category specified in rule 1 shall be notified in the Gazette of India, together with the name of the applicant, the title of the film, the name of the producer and the length of the film as approved and its category.

S. M. MURSHED, Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

SUBJECT :—*Appointment of a Task Force to examine the Planning and Development of small and medium sized cities and towns.*

New Delhi, the 15th October 1975

RESOLUTION

No. K.14011/45/75-UD.II.—The problems of un-planned urban growth, particularly in small and medium towns, and the need to review the existing laws relating to local administration and urban development in such towns have been engaging the attention of Government. It has, therefore, been decided to appoint a Task Force to go into the various aspects of planning and development of small and medium sized cities and towns. The Task Force will consist of the following :—

1. Prof. Bijit Ghosh,
School of Planning and
Architecture, New Delhi.

Convener

- | | |
|--|--------|
| 2. Prof. Deva Raj,
Former Director,
Centre of Urban Studies,
Indian Institute of Public
Administration, New Delhi. | Member |
| 3. Prof. Girijapati Mukherji,
Former Chairman, Town and
Country Planning Organisation,
New Delhi. | Member |
| 4. Shri R. Gopalaswamy,
Joint Secretary,
Ministry of Works and Housing and
Chairman, Town and Country
Planning Organisation,
New Delhi. | Member |

2. The terms of reference of the Task Force will be the following :—

- To generally assess the pattern of evolution of towns and cities since Independence.
- To examine laws relating to local administration and urban development and to suggest suitable modifications to these laws, keeping in view the need to assist in the planned growth of small and medium towns.
- To formulate guidelines and regulations relating to matters such as zoning, setbacks, building control and such other relevant matters.

3. The Town and Country Planning Organisation, New Delhi, will provide necessary secretarial and technical assistance.

4. The Task Force is requested to submit its report within six months.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India and all State Governments and Union Territories etc.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. R. IYER, Under Secy.

New Delhi, the 10th October 1975

No. Q-16011/1/72-WE.—In pursuance of Rule 3(b) read with Rules 4(iv) and (vi) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby appoints Prof. V. B. Singh, Department of Economics, Lucknow University, Lucknow as a Member of the Central Board for Workers' Education, in place of Shri S. N. Ranade of University of Delhi, with effect from the date of issue of this Notification.

2. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour and Employment Notification No. E&P-4(24)/58 dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India Part I Section 1, dated December 20, 1958/ Agrahayana 29, 1880 as amended from time to time.

For the existing entry:

"13. Shri S. N. Ranade,
Director,
Delhi School of Social Work,
Delhi."

the following entry shall be substituted.

"13. Prof. V. B. Singh,
Department of Economics,
Lucknow University,
Lucknow."

J. C. SAXENA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd October 1975

No. V-18025/14/75-FAC.—In modification of the Government of India's notification No. 2/11/70-FAC, dated the 31st October, 1970, Lieutenant General K. S. Garewal is hereby nominated under Rule 7(b) of the Rules and Regulations of the National Safety Council, to be the Chairman of the Board of Governors of the said Council, *vice* Shri Bagaram Tulpule, resigned.

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.